

मौसम



अधिकतम
तापमान
32. C
27. C

न्यूनतम तापमान

बाजार

सोना 95.770g
चांदी 97.030kg

यमन में हूती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजराइली एयरस्ट्राइक

2000 किमी दूर 20 फाइटर जेट्स से 50 थिकानों पर बम गिराए, एयरपोर्ट अटैक का बदला

एजेंसी

सना, इजराइली सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर खुदैह पर सोमवार रात भीषण बमबारी की। सेना के मुताबिक हमले में 20 इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसके लिए विमानों ने 2000 किमी की दूरी तय की। हमले में हूदैह पोर्ट और बाजिल क्रीट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इजराइल फिफेंस फोर्स के

मुताबिक फाइटर जेट्स ने कम से कम 50 टार्गेट पर बम गिराए। इजराइल का यह हमला एक दिन पहले हूती विद्रोहियों के तेल अवैश्व मेन-गुरियन एयरपोर्ट हमले के जवाब में किया गया। मिसाइल हमले में कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद इजराइल ने इसका बदला लेने का एलान किया था। हूती विद्रोही बोले- इजराइल को जवाब देंगे हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजराइली हमले में कम से कम 21 लोग घायल हो गए हैं। हूती विद्रोहियों के



मीडिया विभाग के चीफ नसरुद्दीन आमेर ने कहा कि वे इस हमले का

जवाब देंगे। इजराइली हमले उहने नहीं रोक पाएंगे। उहनोंने यह भी दी बात किया कि यह हमला इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। हालांकि, एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन ने इन हमलों में भाग नहीं लिया। इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला हूती शासन की अर्थव्यवस्था और उसका सैन्य मिर्मांग के लिए एक झटका है। बाजिल क्रीट फैक्ट्री उके लिए एक अहम अधिक संसाधन के रूप में काम करती है और

इसका उपयोग सुरंगों और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है। सेना ने कहा कि हूदैह बंदरगाह और अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि 'इंग्रीजी विद्रोही' सैन्य जरूरतों के लिए उत्करणों और दूसरे आतंकी मकसद के लिए उत्तरायली सेना ने कहा कि यह हमला हूती शासन की अर्थव्यवस्था और उसका सैन्य मिर्मांग के लिए एक झटका है। बाजिल क्रीट फैक्ट्री उके लिए एक अहम अधिक संसाधन का पहला काम होने के बाद यमन पर हमला हूतीयों के

इजराइल के खिलाफ बार-बार किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। हूती विद्रोही ने सोमवार दो बाद से करने के लिए एक बार कैबिनेट ने सोमवार दो बाद से फैक्ट्रे पर मंजूरी दी। इसमें गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने और पूरे इलाके पर कंट्रोल करने का प्लान शामिल है। एयरपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि उपर्याप्त है कि इसे अगले सात दिन लेबनान और बेबा घाटी में हजबुल्लाह के ठिकानों पर कहिए। इसके अलावा उहनोंने लेबनान की सीमा से सटे सीरिया के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

ट्रम्प ने यूएन की 19 हजार करोड़ की मद्द रोकी भारत पर पाक के आरोप यूएनएससी में खारिज तीन हजार कर्मियों की छंटनी का प्लान; सिर्फ 5 महीने की सैलरी बची

एजेंसी



न्यूयॉर्क, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र (शून) को मिलने वाले 19 हजार करोड़ का फंड रोक रखा है। इसमें से कुछ पैसा बाड़ने पर सामान वाले कर्मियों को भी है। ट्रम्प के फंड नहीं देने से यूएन कंगाली के मुहरों पर खड़ा है। बजट संकेत इतना पांचवां है कि अगले हालात नहीं बदले, तो 5 महीने के बाद कर्मचारियों को तात्काल देने के पैसे भी नहीं होंगे। बजट संकेत के चलते यूएन अपने कई विभागों से 3000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। अमेरिका अगर इस साल भी अपनी जरूरी वित्तीय मदद

नहीं चुकाता तो 2027 तक उसे संयुक्त राष्ट्र महासाधा में बोले देना अधिकार गंवाना पड़ सकता है। वठ चार्टर के अनुच्छेद 19 के मुताबिक, कोई भी

सदस्य देश जो दो साल तक अपनी अनिवार्य सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं करता तो वह महासाधा में बोलिंग का अधिकार खो देता है। इरान, वेनेजुएला, जैसे देशों का अनिवार्य भुगतान न करने के कारण बोलिंग अधिकार करोड़ गंवाना पड़ा है। हालांकि, ऐसा होने पर यूएन की साथी को भी झटका लग सकता है। यूएन के बजट में चीन की विस्तृती 20% है। चीन ने बीते साल विस्तृदारी देने में देरी की। 2024 में उसका फंड 27 दिसंबर को आया। यूएन उस फंड को खर्च नहीं कर सकता। नियमों के तहत पैसा खर्च न होने पर उसे सदस्य देशों को वापस करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र को मिलने

वाला पैसा सदस्य देशों की आर्थिक क्षमता के अनुसार तय होता है। यह फंडिंग अमरतौर पर साल की शुरूआत यानी जनवरी में मिल जानी चाहिए, लेकिन 2024 में करीब 15% भुगतान दिसंबर तक नहीं आया। 2024 में सात हजार करोड़ रुपए की राशि 41 देशों पर बकाया रही। इसमें अमेरिका, अर्जेटीना, वियेन्सों पर पाकिस्तान से सवाल आया। जैसे देशों में पूर्वोत्तर एशिया के बाद यूएन एसपीसी है। इसमें बोलिंग के लिए एक बड़ा बदला आया। यूएन उस फंड को खर्च नहीं कर सकता। नियमों के तहत पैसा खर्च न होने पर कर्मचारी देशों को वापस करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र को बजट और नकदी के स्तर पर कुल 1,660 करोड़ का सीधा घाटा हुआ।

वाला पैसा सदस्य देशों की आर्थिक क्षमता के अनुसार तय होता है। यह फंडिंग अमरतौर पर साल की शुरूआत यानी जनवरी में मिल जानी चाहिए, लेकिन 2024 में करीब 15% भुगतान दिसंबर तक नहीं आया। 2024 में सात हजार करोड़ रुपए की राशि 41 देशों पर बकाया रही। इसमें अमेरिका, अर्जेटीना, वियेन्सों पर पाकिस्तान से सवाल आया। जैसे देशों में पूर्वोत्तर एशिया के बाद यूएन एसपीसी है। इसमें बोलिंग के लिए एक बड़ा बदला आया। यूएन उस फंड को खर्च नहीं कर सकता। नियमों के तहत पैसा खर्च न होने पर कर्मचारी देशों को वापस करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र को बजट और नकदी के स्तर पर कुल 1,660 करोड़ का सीधा घाटा हुआ।

चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जलसंकट

भारत ने दो बांध बंद किए, पाक के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर असर

एजेंसी



पिंजीरिया, पाकिस्तान और लीबिया नहीं देशों में कर्मियों की संख्या 20 फीसदी तक घटाएगा। अमेरिका अगर इस साल भी अपनी जरूरी वित्तीय मदद

पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे घरों की 80% आवादी पेवजल वाले शहरों की 80% आवादी पेवजल के लिए चिनाब के सतही पानी पर निर्भर है। सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जारी कि भारत के इस कदम से खरीफ के फसलों के लिए पानी में 21% की कमी आएगी। पाकिस्तानी संघर्षों में से 21 नोवेंबर के बाद यूएन एसपीसी के लिए पानी में 21% की कमी आएगी। पाकिस्तानी बांधों के लिए तरसना की तरफ से इन नियमों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। वहां की आर्थिक विश्वासी बोलते हैं।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि जल समझौता रोक दिया है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नियमों का पानी बांटने को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत को तीन पूर्वी नियमों (रावी, ब्यास और सतलज) का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान की तीन पश्चिमी नियमों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर नि�र्भर है। अब भारत की तरफ से इन नियमों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। वहां की आर्थिक विश्वासी बोलते हैं।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि जल समझौता रोक दिया है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नियमों का पानी बांटने को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत को तीन पूर्वी नियमों (रावी, ब्यास और सतलज) का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान की तीन पश्चिमी नियमों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर नि�र्भर है। अब भारत की तरफ से इन नियमों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। वहां की आर्थिक विश्वासी बोलते हैं।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि जल समझौता रोक दिया है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नियमों का पानी बांटने को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत को तीन पूर्वी नियमों (रावी, ब्यास और सतलज) का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान की तीन पश्चिमी नियमों (सिंधु, झेलम और चिनाब) का इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर नि�र्भर है। अब भारत की तरफ से इन नियमों का पानी रोक देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। वहां की आर्थिक विश्वासी बोलते हैं।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि जल समझौता रोक दिया है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नियमों का पानी बांटने को लेकर सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत को तीन पूर्वी नियमों (रावी, ब्यास और सतल

